मणिपुर की स्थिति

आरोप निराधार

मणिपुर में अधिकारों के कथित उल्लंघन पर भारत ने अमेरिका की रिपोर्ट को 'अत्यधिक पूर्वाग्रही' बताया है। अमेरिका द्वारा भारत पर खासकर मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाने के फौरन बाद भारत ने कठोरता से उसकी विदेश विभाग की रिपोर्ट की आलोचना की है। भारत सरकार ने रिपोर्ट को 'अत्यधिक पूर्वाग्रही' बता कर खारिज करते हुए कहा है कि इसमें 'जमीनी यथार्थ के प्रति व्यापक गलतफहमी' स्पष्ट रूप से दिखती है। भारत ने अमेरिका को उसके अपने देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर आईना दिखाते हुए अमेरिका में भारतीय छात्रों की हालिया हत्याओं पर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट की प्रकृति को 'अत्यधिक पूर्वाग्रही' बताते हुए कहा कि रिपोर्ट मणिपुर की स्थिति को भ्रामक तरीके से पेश करते हुए अपनी सीमाओं के भीतर मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित करने के भारत के प्रयासों के प्रति 'समझदारी की कमी' प्रदर्शित करती है।

रिपोर्ट केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है और उसमें अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने संभवत: निकट अतीत में भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन-बीबीसी के कार्यालयों पर मारे गए छापों का उल्लेख है। आरोप लगाया गया है कि इन छापों का विस्तार पत्रकारों तक किया गया, जबकि उनका संगठन के वित्तीय मामलों से कोई लेनादेना नहीं था। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने बीबीसी-निर्मित डाक्यूमेंट्री पर

प्रतिबंध लगाने के लिए आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया। रिपोर्ट में स्थानीय मानवाधिकार संगठनों व अल्पसंख्यक राजनीतिक पार्टियों के सरोकारों तथा हिंसा के प्रति सरकार की कथित 'विलंबित प्रतिक्रिया' और मणिपुर में उपयुक्त मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में विफलता से प्रभावित समुदायों का भी उल्लेख है। इसमें सिविल सोसाइटी संगठनों, सिख व मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों तथा राजनीतिक विपक्षी समूहों के खिलाफ दुष्प्रचार रणनीतियों के उदाहरण दिए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिक्रिया प्रशंसनीय है जो भारतीय संप्रभुता की सीमाओं की रक्षा करते हुए यह संदेश देती है कि किसी देश को भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। पिछले दशक में भारत सरकार ने लगातार सुनिश्चित किया है कि कोई अन्य देश भारत के आंतरिक मामलों पर अनावश्यक टिप्पणी न करे। उसने अपनी रणनीतियों से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी 'घरेलू नीतियों' के बारे में किसी अन्य देश या संगठन के दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया अपनी संप्रभुता की रक्षा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मानवाधिकारों का सम्मान करने के देश के प्रयासों का सही अंतरराष्ट्रीय आकलन हो। भारत ने लगातार कहा है कि वह अपने जीवन्त कानूनी ढांचे तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघन के किसी वैध सरोकार को संबोधित करने के लिए तैयार है। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है और अब अधिकांश देश भारत के प्रति 'निहित स्वार्थी' संगठनों अथवा 'राजनीति प्रेरित' पूर्वाग्रही टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भी सोचना चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट जारी करने से पहले उसे शानदार द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए भारत से समुचित संवाद करना चाहिए था।

लोकसभा चुनाव में एआई की भूमिका

व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं तक पहुंचने के साथ डीपफेक वीडियो तक, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई का प्रभाव स्पष्ट है। इससे नई खोजें तथा नैतिक आयाम प्रभावित हो सकते हैं।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वर्तमान लोकसभा चुनाव में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई के प्रभाव को लेकर चिन्ता का माहौल है। व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं तक पहुंचने के साथ डीपफेक वीडियो तक, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई का प्रभाव स्पष्ट है। इससे नई खोजें तथा नैतिक आयाम प्रभावित हो सकते हैं। आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई को 2024 के लोकसभा चुनाव में 'गेम चेंजर' माना जा रहा है। इसने चुनाव अभियान की परंपरागत रणनीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। भारत के बदलते परिदृश्य में लगातार चुनाव प्रचार के तरीकों में व्यापक परिवर्तन आया है। वह युग बीत गया जब विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उनके घरों तक जाते थे तथा चाय पीने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत करते थे। लेकिन पिछले पांच साल में ही अब राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार तकनीकी रूप से ज्यादा उत्कृष्ट तरीके अपनाने लगे हैं। सोशल मीडिया ने 2014 के लोकसभा चुनाव में केन्द्रीय भूमिका निभाई थी। लेकिन एआई के आविष्कार तथा 'डीपफेक वीडियो' का संभावित प्रयोग भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं। डीपफेक वीडियो सच और झूठ के बीच विभाजक रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं। चिन्ता की बात है कि ऐसे वीडियो व अन्य तकनीकों से चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के विश्वास और उनकी निष्ठा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा चुनाव में एआई के संभावित उपयोग व दुरुपयोग पर गंभीर नजर रखते हुए सभी संबंधित पक्षों को पूरी सावधानी बरतनी होगी।

राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही एआई की शक्ति समझ ली है। वे एआई का प्रयोग मतदाताओं का डेटा विश्लेषण के लिए कर रहे हैं जिससे उनको प्रभावी चुनाव प्रचार रणनीतियां बनाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही एआई-संचालित 'चैटबोट' व 'वर्चुअल असिस्टेंट' का प्रयोग सोशल मीडिया पर मतदाताओं से संपर्क करने, उनके सवालों का फौरन जवाब देने तथा उनके सरोकारों को संबोधित करने के लिए किया जा रहा है। एआई तकनीक का प्रयोग अनेक प्रकार से चुनाव प्रक्रियाओं में सहायता कर सकता है। इसके साथ ही एआई चुनाव नतीजों का पूर्वानुमान भी कर सकता है। एआई-संचालित चैटबोट और वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअल मीडिया से सीधे संवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही एआई चुनाव में धोखाधड़ी पर विराम लगाने के साथ ही राजनीतिक विज्ञापन अभियानों को भी स्वरूप दे सकते हैं। इस प्रकार वे वित्तीय रूप से आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन भी कर सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अब व्यक्तिगत मतदाताओं से संपर्क करने के लिए अपने मीडिया सेलों को परिष्कृत रूप दे सकती हैं। इसके साथ ही वे एआई के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने का काम भी कर सकती हैं। भारत में आज देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग करती है। वर्ष 2025 तक इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ कर 900 मिलियन तक पहुंच सकती है। इस प्रकार भारत के वर्तमान और भावी चुनाव लगभग 500 करोड़ रुपये का बाजार बनाएंगे। भारत की राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एआई का प्रयोग कर रही हैं। कांग्रेस और भाजपा ने पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों में भी एआई का प्रयोग किया था। इसके चलते पहली बार राजनीतिक प्रचार अभियानों में फर्जी वीडियो व पैरोडियों का प्रयोग किया गया था। भाजपा, कांग्रेस, आप, द्रमुक व अन्नाद्रमुक ने अपने समर्थकों से संपर्क करने तथा उनको उपयुक्त जानकारियों से लैस करने के लिए एआइ का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, भाजपा ने एआई के प्रयोग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों का आठ क्षेत्रीय भाषाओं में त्वरित अनुवाद किया। लेकिन एआई की क्षमताओं को देखते हुए कुछ चुनाव अभियानों में कुछ अभियानकर्ताओं ने एआई-निर्मित वीडियो का दुरुपयोग भी किया जिनमें डीपफेक वीडियो शामिल हैं। इन तकनीकों का प्रयोग भ्रामक सूचनायें फैलाने के लिए किया गया। इन भ्रामक वीडियो से 18-25 वर्ष आयुवर्ग वाले युवाओं को निशाना बनाया गया और इनका साझा वाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों पर किया गया। भारत में राजनीतिक पार्टियां पहले से ही मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग करती रही हैं। वे सोशल मीडिया पर फर्जी छवियां और वीडियो प्रचारित करती हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भ्रामक तस्वीर साझा की। इसी प्रकार भाजपा ने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया। तमिलनाडु में द्रमुक व अन्नाद्रमुक ने इस चुनाव में मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने मृत नेताओं की रिकार्डिंगों का प्रयोग किया। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी अपने चुनाव अभियानों में एआई तकनीक का प्रयोग किया। एक वीडियो में आल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन-एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू भक्ति गीत गाते दिखाया गया। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनेक क्षेत्रीय नेताओं ने भी एआई तकनीकों का प्रयोग किया। इनमें अखिलेश यादव, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी शामिल हैं।

आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई का दुष्टतापूर्ण व आपराधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना गंभीर चिन्ता का विषय है। उत्कृष्ट एआई के माध्यम से अब किसी व्यक्ति की नकल करना बहुत आसान हो गया है जिसमें मतदाता व राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार शामिल हैं। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया में सेंध लगाना तथा छेड़छाड़ करना भी संभव हो गया है। एआई के बढ़ते उपयोग तथा इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए स्वच्छ व पारदर्शी चुनाव प्रक्रियायें सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम-विनियम बनाने की आवश्यकता पहले के किसी भी समय की तुलना में ज्यादा जरूरी हो गई है। इससे दर्शकों को संभावित खतरों के प्रति सावधान किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को संबोधित करने का तरीका भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस पर व्यापक व कठोर निगरानी रखना जरूरी है। राजनीतिक अभियानों में एआई के प्रयोग से निजता के उल्लंघन, संभावित असमान प्रतियोगिता तथा दुष्प्रचार की आशंकाओं के बारे में चिन्तायें पहले के किसी भी समय की तुलना में गहरी हुई हैं। इसलिए आज पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियमों-विनियमों का क्रियान्वयन होना चाहिए।

सरकारों को चुनाव प्रक्रिया में न्याय व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई-नियमन की दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करनी होगी। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पहले ही सोशल मीडिया कंपनियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। इससे मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और निष्ठा के बारे में मतदाताओं में विश्वास पैदा हुआ है। चुनाव आयोग को 2024 लोकसभा चुनाव में एआई-सृजित सूचनाओं के नियमन के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। इन दिशानिर्देशों में चुनाव प्रचार अभियानों तथा मतदाताओं के डेटा विश्लेषण में एआई के नैतिक प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम बनाए जाने जरूरी हैं। इन नियमों में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया में न्याय व पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इन नियमों के बिना चुनाव परिणामों की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं।

जहां एआई के बारे में वैध चिन्तायें हैं, वहीं यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि यह सकारात्मक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एआई-सृजित तकनीकों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने की क्षमता है। तकनीकों की व्यापक स्वीकार्यता के साथ ही वे ई-चुनाव का रास्ता खोल सकती हैं। इस प्रकार भीवष्य में आनलाइन चुनाव के साथ ही पारदर्शी व जवाबदेह चुनाव प्रक्रिया सामने आ सकती है। इस सकारात्मक परिवर्तन की संभावना आशा और उम्मीद पैदा करती है तथा मतदाताओं को भावी चुनावों के बारे में आश्वस्त करती है।

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग

अब समय आ गया है कि अपनी पहचान बनाने के लिए नियामक बाधाओं को दूर किया जाए

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

भारत में निवेश के खिलाफ विदेशी निवेशकों द्वारा उद्धृत सबसे आम कारणों में से एक अत्यधिक जटिल नियामक प्रक्रियाएं और ओवरलैपिंग अनुपालन की बहुलता है। इस बैंडबाजे में शामिल होने वाले नवीनतम व्यक्ति ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू हैं। मंत्री एक पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे थे कि नए युग की प्रौद्योगिकी, बिल्डिंग ब्लॉक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ताइवानी कंपनियां भारत के निरंतर स्वागत के लिए तैयार क्यों नहीं हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माण सुविधाओं का घर है, जो मोबाइल फोन से लेकर उपग्रहों तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। वू ने पत्रकार के साथ अपनी बातचीत के दौरान कहा, भारत अपने प्रशासनिक ढांचे में बोझिल है और भारत सरकार को देश में आने वाले सेमीकंडक्टर निवेशकों की मदद के लिए सभी प्रकार के कानूनों और नियमों को सुव्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने उसी साक्षात्कार में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कुशल इंजीनियरों की कमी के बारे में भी बात की, हालांकि भारत में चिप-डिज़ाइनिंग प्रतिभाओं की कमी नहीं है।

श्री वू ने जो उजागर किया, वह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि, यह भारत में रुचि रखने वाले कई अन्य संभावित निवेशकों की समान चेतावनी है। इस लेखक ने कई नई और उभरती प्रौद्योगिकी निर्माण कंपनियों के कई उच्च-रैंकिंग अधिकारियों से बात की, जिन्होंने भारत में जटिल समय लेने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में

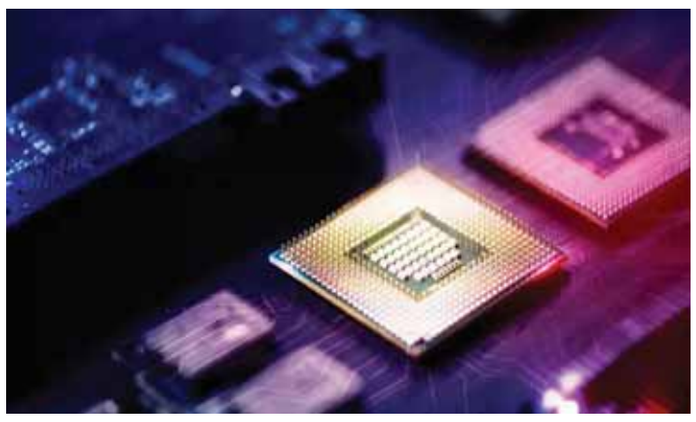

शिकायत की और सिंगापुर, वियतनाम आदि जैसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसे दोहराया। कठिन नियामक व्यवस्था के माध्यम से संभावित निवेशकों की सहायता के लिए, वर्तमान सरकार के शासन के प्रारंभ में, इन्वेस्ट इंडिया (एक सार्वजनिक-निजी संयुक्त उद्यम) नामक एक नया विभाग बनाया गया था। यहां तक कि सेमीकंडक्टर के लिए, जहां भारत पसंदीदा संभावित भागीदार है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के रूप में एक समर्पित व्यापार प्रभाग बनाया गया है।

बिडेन प्रशासन द्वारा जारी हालिया व्यापार नीति एजेंडा 2024 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगस्त 2022 में वार्ता जनादेश की घोषणा के बाद से, दोनों पक्षों ने जितनी जल्दी हो सके प्रगति करने के लिए बैठकों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनाया है। जून 2023 में, आईटी और टेकरो ने पहल के तहत पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में कई व्यापार क्षेत्रों में उच्च-मानक प्रतिबद्धताएं और आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम शामिल हैं, जिनमें सीमा शुल्क प्रशासन और व्यापार सुविधा, अच्छी नियामक प्रथाएं, घरेलू विनियमन सेवाएं, भ्रष्टाचार विरोधी और छोटे और मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं, दोनों के बीच साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। दो देश.

अमेरिका चीन के विकल्प के रूप में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में विकसित होने की भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, जो अधर में लटके हुए थे, औपचारिक व्यापार नीति मंच के अस्तित्व में आने के बाद पिछले दो वर्षों में सक्रिय हो गए हैं, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर नियमित बैठकें हुई हैं। 2024 के व्यापार नीति एजेंडा दस्तावेज़ में, अमेरिका का उल्लेख है, हम कामकाजी लोगों के लाभ के लिए व्यापार संबंधों को गहरा करने की दृष्टि से, कई क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद परिणामों के लिए बढ़ी हुई भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने महत्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें हमारी सरकारें आर्थिक रूप से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी रोडमैप विकसित करने का इरादा रखती हैं।

हितों के अभिसरण और अर्धचालक की दौड़ में भारत में निवेश और समर्थन करने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों और सहयोगियों की इच्छा को देखते हुए, अगली सरकार अपने 100-दिवसीय एजेंडे में नियामक बाधाओं को दूर करने को शामिल करने के लिए अच्छा कर सकती है। यह घोषित विकिस्ट भारत लक्ष्य की दिशा में एक अच्छी शुरुआत होगी।

आप की बात

पित्रोदा का विचार

कॉंग्रेस के सैम पित्रोदा का विचार है कि भारत मे भी अमरीका जैसा विरासत कर होना चाहिए। यह विचार तर्क संगत नहीं है क्योंकि दुनिया में आज तक कहीं भी निजी संपत्तियों के पुनर्वितरण से असमानता दूर नहीं हुई है अपितु रूस और कंबोडिया में इस अवधारणा के कारण लाखों लोग मारे गये थे। आर्थिक गतिविधि के सहभागी आधार को व्यापक बनाने से ही सभी को लाभ होगा तथा ऐसी स्थिति में ही लोकतंत्र और निजी संपत्ति साथ-साथ चल कर आगे बढ़ सकेंगे। संपत्ति का कट्टरपंथी पुनर्वितरण ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी क्रांतियों की विशेषता रही है जिसने अपनी ही जनता के बहुसंख्य वर्ग को भारी कष्टों में डाला था। इन गलतियों से सबक लेकर ही पहले चीन तथा बाद में रूस ने निजी उद्यमों व निजी संपत्ति को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन विडंबना है कि अपने जन्म से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय पूंजीपतियों, जैसे टाटा, बिड़ला, डालमिया की पैरोकारी करने वाली कांग्रेस आज ऐसे अति-वामपंथियों के जाल में फंस गई है जो स्वयं अपने मूल देशों रूस और चीन में अप्रासांगिक हो गए हैं। लगता है कि वर्तमान कांग्रेस बिना सत्ता के इस तरह तड़प रही है कि उसकी बुद्धि और विवेक पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उसे अपने इतिहास पर गौर करना चाहिए।

– **परमवीर केसरी,** मेरठ

मसालों पर प्रतिबंध

सिंगापुर और हांगकांग में दो भारतीय कंपनियों के कुछ मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसालों में इथाईलीन ऑक्साइड नामक विषाक्त पदार्थ अधिक मात्रा में पाया गया है। हमारे देश में भी इन कंपनियों के मसाले का भरोसे के साथ घर-घर में प्रयोग है। ऐसा लगता है कि उनके लिए मानक निर्धारित करने वाली संस्था एफएसएआई सिर्फ फीस लेकर सर्टिफिकेट दे देती है और खाद्य पदार्थों की दोबारा व नियमित जांच नहीं होती है। मसाले में प्रयुक्त कच्चे माल के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों आदि का प्रयोग होने से वे जहरीले हो जाते हैं। मसालों की तरह ही अन्य खाद्य पदार्थों में भी ऐसे विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि विदेशों की तरह देश में पैकेटबंद या खुले बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर गुणवत्ता मानक कठोर नहीं हैं। आज जब भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा विकसित देश बनने की दौड़ में शामिल है तो उसे अन्य विकसित देशों की तरह ही आम जनता के उपयोग वाली खाद्य सामग्रियों समेत सभी चीजों पर दुनिया के कठोरतम माने जाने वाले अमेरिकी मानक लागू करने चाहिए। मसालों पर प्रतिबंध का यही उचित सबक होना चाहिए।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

भारत-पाक संबंध

पाकिस्तानी व्यापार जगत ने देश के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से भारत के साथ व्यापार-व्यवसाय शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि व्यापार संबंध फौरन बनाए जाएं ताकि संकटग्रस्त पाकिस्तान को मदद मिल सके। पाकिस्तानी दिग्गज कंपनी आरिफ हबीब समूह के प्रमुख का कहना है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से व्यापार वार्ता शुरू करे ताकि इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है और देश की जनता परेशान है। इसीलिए पाकिस्तान फिर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार कर 2014 के पहले की तरह व्यापार व वाणिज्य बहाल करना चाहता है। लेकिन यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान हजारों साल भारत से युद्ध करने की प्रतिज्ञा के साथ भारतीयों को काफिर कहता है तथा अपने देश के हिंदुओं का भयानक दमन कर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ता है। पाकिस्तान अब भी कश्मीर में आतंकवादी भेजता है तथा हर मंच पर भारत-विरोधी जहर उगलता है। ऐसे में पाकिस्तानी व्यापारी चाहे जो कहें, भारत-पाक संबंध सामान्य होना तथा व्यापार व वाणिज्य बहाल होना वर्तमान परिस्थितियों में लगभग असंभव ही लग रहा है।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

आंदोलन का खामियाजा

पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू रेलवे स्टेशन में जारी किसान आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को अकारण सजा भुगतना पड़ रही है। लगभग एक सप्ताह से रोज 40-50 ट्रेन रद्द की जा रही है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को ज्यादा पैसा देकर बस या अन्य साधन से अपने गंतव्य जाने में भारी परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि पार्सल बुकिंग में भी 50 प्रतिशत कमी व यात्रियों की कमी से रेलवे को भी भारी घाटा हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण मरीज को उपचार हेतु और छात्रों को पढ़ाई व इंटरव्यू आदि कार्य से बाहर जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे परिचालन में बाधा डालना अपराध है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसानों का आंदोलन ऐसे समय अनुचित है जब पूरा देश लोकसभा चुनाव की गतिविधियों में व्यस्त है। उनको सोचना चाहिए कि चाहते हुए भी कोई सरकार उनकी मांगों पर इस समय निर्णय नहीं ले सकती है। वास्तव में स्वयं को अराजनीतिक कहने वाला किसान आंदोलन कुछ नेताओं के निहित राजनीतिक स्वार्थों की उपज है। इस आंदोलन का खामियाजा जनता भुगत रही है।

– **बी एल शर्मा,** उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 62

अधिक प्रतिस्पर्द्धा की दरकार

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह उन मौजूदा 'लघु वित्त बैंक' या एसएफबी के लिए नए नियम जारी किए जो खुद को नियमित यानी 'यूनिवर्सल' बैंक में बदलने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हैं कि क्या कोई मौजूदा एसएफबी तुरंत इस प्रक्रिया का लाभ उठा पाएगा या नहीं लेकिन यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इसके माध्यम से स्पष्ट नीतियां पेश की गई हैं जिसका लक्ष्य काफी लंबे समय से तय है।

इस बदलाव से गुजरने पर एसएफबी को निश्चित रूप से कुछ लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर वे प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के अपने स्तर को कम कर सकते हैं। इससे उनकी पूंजी की आवश्यकता कम होगी और ज्यादा मुनाफा बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए आरबीआई के पात्रता नियम अपेक्षाकृत ज्यादा सख्त हैं और कई एसएफबी इसके पात्र नहीं हो पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि लघु वित्त बैंक सूचीबद्ध हों और वे पांच वर्षों से संचालित हो रहे हों। इसके साथ ही उन्हें नियामक की नियमित जांच प्रक्रिया में भी सफल होना होगा।

इसके अलावा इन एसएफबी को पिछले दो वर्षों में शुद्ध लाभ दर्ज करना चाहिए और इनकी हैसियत कम से कम 1,000 करोड़ रुपये तक होनी चाहिए। एयू एसएफबी को छोड़कर बाकी सभी मौजूदा एसएफबी की हैसियत अभी 1,000 करोड़ रुपये से कम है। एयू एसएफबी के फिनकेयर एसएफबी के साथ विलय किए जाने की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी और इससे दक्षिण भारत में इसके लिए नए क्षेत्र खुल जाएंगे। हालांकि व्यापक प्रक्रिया एक अच्छी खबर के संकेत दे रही है। इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य, स्पष्ट नियामक लक्ष्यों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने से जुड़ा होना चाहिए। एसएफबी श्रेणी की घोषणा 2014 में की गई थी और ज्यादातर एसएफबी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनएफबीसी) से ही तैयार किए गए थे। अब उनके पास यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए एक रास्ता बनता दिख रहा है। निश्चित तौर पर उनके पास सुरक्षा, विश्वसनीयता और नियामकीय निरीक्षण की एक स्पष्ट सीढ़ी है जिसका पालन करके वित्तीय योजनाओं से जुड़ा क्षेत्र एक नियमित बैंक बन सकता है। बैंकिंग नियामक के लिए वास्तव में बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए।

शोध से पता चला है कि भारत में 1998 से शुरू हुए बैंक सुदृढ़ीकरण के दौर में मौद्रिक नीति की प्रसार क्षमता में अच्छी-खासी गिरावट आई है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि बाजार की बड़ी ताकत से किसी बैंक के वैकल्पिक वित्तीय फंडिंग के स्रोत बढ़ जाते हैं। एसएफबी श्रेणी मूल रूप से सभी तक वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने के मकसद से तैयार की गई थी। निश्चित रूप से यह शोध का विषय है कि उन्होंने उस उद्देश्य की पूर्ति की है या नहीं।

हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है कि एसएफबी को परिभाषित करने वाले नियामकीय वातावरण से उभरे बैंक, यूनिवर्सल बैंकिंग के दायरे का विस्तार करने में भी मदद करेंगे, खासतौर पर यह देखते हुए कि उन्हें उन लोगों से बैंकों की जमाएं बढ़ाने के बारे में विशिष्ट जानकारी है जो बैंकिंग सेवाएं से वंचित रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जमा वृद्धि को भविष्य में प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। स्टैंडर्ड ऐंड पूअर के हालिया शोध से पता चला है कि बैंकों में ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि के मुकाबले 2-3 फीसदी अंक अधिक है। बैंकिंग क्षेत्र के कुछ लोगों का तर्क है कि यह अन्य रुझानों का एक स्वाभाविक परिणाम है। उदाहरण के तौर पर घरेलू वित्तीय बचत पर दबाव है और म्युचुअल फंड जैसे वैकल्पिक निवेश स्रोतों का प्रदर्शन आकर्षक रहा है। इसी बीच, हाल के दिनों में बैंकों में जमा पर रिटर्न वास्तविक रूप में बहुत कम रहा है। हालांकि, ऋण की मांग लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर, एसऐंडपी के अनुसार, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से ऋण वृद्धि 1.5 गुना अधिक है, जबकि जमा वृद्धि बाजार मूल्य पर जीडीपी के अनुरूप है।

ऐसे में जब तक जमा वृद्धि में तेजी नहीं लाई जाती है, तब तक ऋण वृद्धि में गिरावट आ सकती है। इसका व्यापक अर्थव्यवस्था, समग्र निवेश और वृद्धि पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। बैंकिंग आधार के विस्तार पर ध्यान देने के साथ अधिक से अधिक बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका है।

चुनावी लड़ाई में आगे लेकिन मुद्दा तय करने में पीछे

जिन चुनावों में 'लहर' होती है, उनमें अक्सर उत्साह चरम पर होता है, एक किस्म का पूर्वानुमान होता है, बेहतर भविष्य की आशा होती है और यहां तक कि प्रतिशोध भी नजर आता है।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

लोक सभा चुनावों के प्रचार अभियान का तकरीबन आधा दौर पूरा हो चुका है और ऐसा लगता है, और मैं थोड़ी घबराहट के साथ ऐसा कह रहा हूं कि बहुत कम चीजें सामने आई हैं। घबराहट इसलिए कि मेरी दलील इस बात पर टिकी है कि इस अभियान में अग्रणी नजर आने वाले अभियान को अब तक कोई दिशा नहीं दे पाए हैं।

नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का उभार 2012 के आसपास हुआ और तब से उन्होंने भारत में प्रतिस्पर्धी राजनीति की शर्तों को निर्धारित किया है। वर्ष 2014 में सबके लिए अच्छे दिन और '56 इंच सीने' और दुश्मनों (मुख्यतः चीन और पाकिस्तान) के लिए लाल-लाल आंखों की बात की गई। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठाया गया और कहा गया कि इसे लेकर रुख बदलना होगा। आतंकवादियों और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की बात की गई। वर्ष 2024 के चुनावों में हम सात में से तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की चुनावी थीम सामने नहीं आई है। चीन पूरी तरह गायब है और पाकिस्तान का जिक्र भी बहुत कम है।

परंतु इन बातों से इस हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टी अभी भी चुनावी होड़ में दूसरों से काफी आगे है। यही वजह है कि इन चुनावों को लेकर कुछ निरंतरता वाली बातों का सामने नहीं आना दिलचस्प है। यह भी एक वजह है कि इस बार मतदान का प्रतिशत कम है, जबकि अभी तो गर्मियां भी पूरी तरह नहीं आई हैं। यह भी हो सकता है कि भाजपा को अपने सामने कोई प्रतिद्वंद्वी ही नजर न आ रहा हो और इस वजह से उत्साह की कमी नजर आ रही हो। वैसे ही जैसे दो असमान क्षमता वाली क्रिकेट टीमों के बीच एकतरफा मैच होता है। जब नतीजों का अनुमान लगाना इतना आसान हो तो वोट डालने जाना ही क्यों? अगर आप भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोगों तथा मोदी सरकार के समर्थकों से बात करेंगे (मैंने पिछले दिनों बेंगलूरु और उसके आसपास यही किया) तो यही आशंका सामने आएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय चुनावों पर लंबे समय तक नजर रखी होगी वह आपको बताएगा कि ऐसा कभी होता नहीं है। हकीकत में मतदाता का उत्साह अक्सर 'लहर' वाले चुनावों के समय नजर आता है। एक अनुमान, बेहतर भविष्य की और कई बार प्रतिशोध की भावना होती है। इन सभी वजहों से 2024 असाधारण रूप से बिना बिना किसी कहानी के नजर आ रहा है।

आश्चर्य की बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा दौर के सबसे बड़े जादूगर नरेंद्र मोदी ने अब तक इन चुनावों के लिए कोई थीम नहीं पेश की है। उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं पेश किया है जो पहले से सातवें चरण तक चल सके। शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान तक उन्होंने और उनकी पार्टी ने नई-नई थीम पेश कीं और आगे बढ़ गए। ये मुद्दे प्रचार अभियान में एक सप्ताह भी नहीं टिके। विगत तीन सप्ताह के दौरान कांग्रेस तथा विपक्ष के तय मुद्दों ने जिस तरह भाजपा के अभियान को प्रभावित किया है वह भी उल्लेखनीय है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि पहले से सत्ता पर काबिज और चुनाव में आगे चल रहा कोई दल चुनौती देने वाले की बातों पर इस प्रकार प्रतिक्रिया दे। भाजपा ने कड़ी मेहनत से यह प्रतिष्ठा हासिल की है कि वह हमेशा चुनाव प्रचार के लिए तैयार रहने वाला दल है। ऐसे में 2024 का प्रचार इस थीम पर आरंभ हुआ कि नरेंद्र मोदी भारत को अधिक ऊंचा वैश्विक कद दिला रहे हैं। ऐसा जैसा अतीत में किसी ने नहीं दिलाया। जाहिर है संकेत जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की ओर है। इसकी शुरुआत भारत मंडपम से हुई जहां जी20 शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। पूरा आयोजन इस तरह तैयार किया गया था ताकि मोदी को दुनिया का नया नेता दिखाया जा सके और दुनिया के अधिकांश शक्तिशाली देशों के नेताओं ने ऐसा माना भी। हालांकि इसके बाद उस समय झटका भी लगा जब गणतंत्र दिवस के आसपास दिल्ली में क्वाड देशों के नेताओं को एकत्रित करने की योजना फलीभूत न हो सकी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आयोजन का मुख्य अतिथि बनने का न्योता भी ठुकरा दिया था। अब इसमें निज्जर-पन्नून मामले की क्या भूमिका थी या इसने जी20, खासकर भारत और अंग्रेजी भाषी देशों के दरमियान क्या भूमिका निभाई, हम नहीं जानते। यह निष्कर्ष जरूर निकाला जा सकता है कि बढ़ते वैश्विक कद की यह छवि टूटी नहीं है तो भी डगमगाई जरूर है।

चुनाव के पहले के उन सप्ताहों में महिला मतदाताओं को लुभाने का दांव चला गया। निर्वाचन वाली संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए आनन-फानन में पारित कानून इसका हिस्सा था। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई और इसके लिए अगली जनगणना और परिसीमन की प्रतीक्षा करनी होगी। हम कह सकते हैं कि शायद यह 2029 तक भी लागू नहीं हो पाएगा। भाजपा के चुनाव प्रचार में इसका जिक्र भी नहीं सुनने को मिल रहा है। इन चुनावों में भी पार्टी के उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 16 फीसदी है।

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में हुई यह भी चुनावों के लिहाज से मुफीद था। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में भाजपा के 20 नेताओं के करीब 100 भाषणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनमें इस पर जोर या इसका जिक्र नहीं है। यह मुद्दा हाल में उठा जब ऐसे संकेत मिले कि राहुल और प्रियंका गांधी राम मंदिर जा सकते हैं। इस वर्ष चुनाव की तारीख घोषित होने से कुछ सप्ताह पहले भारत रत्न की घोषणा करते समय भी पिछड़े वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दो नेताओं कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को यह सम्मान प्रदान किया गया। ऐसा करके पार्टी ने सामाजिक न्याय का दांव चलने की कोशिश की। परंतु उसके बाद इससे इस बारे में भी ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला। यह जरूर है कि चरण सिंह को यह सम्मान मिलने के बाद उनके पोते ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता जोड़ लिया।

अगर आज चुनाव प्रचार पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इसे प्रतिपक्ष दिशा दे रहा रहा है। शायद कांग्रेस पार्टी भी इस बात से आश्चर्यचकित होगी। बीते तीन सप्ताह में दोनों दलों को अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के घोषणापत्र का उल्लेख करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और उसे लेकर भय उत्पन्न करते हैं, जबकि वह और उनकी पार्टी के नेता अपने घोषणापत्र का बहुत कम उल्लेख करते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को हैदराबाद में घोषणापत्र जारी करते समय कहा कि 'संस्थानों, समाज और संपत्ति' का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद उनका समुचित पुनर्वितरण देश की 90 फीसदी आबादी में किया जाएगा। उन्होंने पुनर्वितरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उनका इशारा यही था। तब से मोदी का प्रचार अभियान उसी पर केंद्रित है। जाहिर है उन्होंने आम महिलाओं के डर का सहारा लेते हुए उनके मंगल सूत्र और स्त्री धन को छीन लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनसे यह लूटना चाहती है। ताजा मुद्दा सैम पित्रोदा के विरासत कर संबंधी बयान से मिल गया। ये डर उचित हैं या नहीं ये अकादमिक मुद्दा है, बशर्ते कि चुनाव अभियान के मध्य में आकर आप यह न सोच रहे हों कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है।

कांग्रेस के अधिकांश नेता तथा उसके विपक्षी सहयोगी दलों के नेता यही कहेंगे कि उनका लक्ष्य मोदी को 272 के नीचे रखने का है। यही वजह है कि अपने पक्ष में माहौल होने के बावजूद चुनाव को लेकर मोदी का रुख विचित्र है। वह अपने 10 वर्ष के प्रदर्शन और 2047 में विकसित भारत बनाने की चर्चा करने के बजाय कांग्रेस के सत्ता में वापस आने का डर दिखा रहे हैं।

सरकार की क्षमता में सुधार की दरकार

अर्थतंत्र
राजेश कुमार

चुनावी राजनीति में राजनीतिक दल प्रायः चुनाव से पहले राजनीतिक घोषणापत्रों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण एवं योजनाएं जनता के समक्ष रखते हैं। परंतु, भारत विकास के जिस चरण में खड़ा है वहां ऐसे घोषणापत्र कदाचित ही सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में तीसरी बार आता है तो कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी विभिन्न खंडों में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। हालांकि, इस स्तंभ का उद्देश्य दोनों दलों के घोषणापत्रों की तुलना करना नहीं है। यहां उद्देश्य अगली सरकार के लिए एक महत्त्वपूर्ण विचार या सोच को रेखांकित करना है जो व्यवहार में लाया जा सके। इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है कि कौन-सा दल या गठबंधन सत्ता में आता है। वर्तमान स्थिति साल 2009 में एक बड़े अर्थशास्त्री से इस लेखक के संवाद की याद दिलाती है। उस वर्ष आम चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार बड़े बहुमत से सत्ता में आई थी। 2009 से पहले कुछ वर्षों में भारत ने शानदार आर्थिक प्रगति की थी और सभी का यह मानना था कि देश वैश्विक वित्तीय संकट से मोटे तौर पर अप्रभावित रहा है।

उस अर्थशास्त्री के साथ हुए संवाद का सारांश यह था कि निजी क्षेत्र ने 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों के बाद सराहनीय प्रदर्शन किया है और अब सरकार को स्वयं में सुधार करना चाहिए। यह तर्क अब भी उतना ही दमदार है जितना 2009 में हुआ करता था। यहां यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि पिछले वर्षों में सरकारी तंत्र में सुधार नहीं हुआ है, परंतु काफी कुछ अब भी किए जाने की आवश्यकता है। विकास से जुड़े कार्य एवं उनके प्रभाव सरकार की क्षमता और चुनौतियों से निपटने की उसके उपायों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन की नई पुस्तक 'एक्सलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंटः अ स्टेट लेड रोडमैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस' में उन कई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जहां सरकारी क्षमता में सुधार की आवश्यकता है। पुस्तक के अनुसार इस क्षमता में सुधार के साथ अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। यह सत्य है कि भारतीय व्यवस्था कुछ चीजें वाकई बेहतर तरीके से करती हैं (उदाहरण के लिए लोक सभा चुनाव आयोजित करना) परंतु कुछ अरुचिकर एवं नियमित कार्य करने में विफल या आंशिक रूप से ही सफल रहती है। देवेश कपूर जैसे शिक्षाविदों ने कहा है कि भारतीय तंत्र निश्चित समय पर होने वाले कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करता है।

देश में कई क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है मगर इस स्तंभ में दो व्यापक पहलुओं पर चर्चा केंद्रित कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत राजकोषीय क्षमता की कमी के कारण प्रभावी ढंग से विकास कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है। इसका कारण यह है कि भारत व्यय के मोर्चे पर विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर सकता है। अर्थव्यवस्था के तेजी से औपचारीकरण के बावजूद इसके कर संग्रह और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का राजस्व पिछले कई वर्षों से स्थिर रहा है और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी कम रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अध्ययन के अनुसार भारत का सकल कर संग्रह इसकी क्षमता से 5 फीसदी से भी अधिक कम रहा है।

अगर यह अंतर पाट दिया जाए तो राजकोषीय क्षमता बढ़ जाएगी और उधारी कम हो सकती है। मगर इस मोर्चे पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा है। जीएसटी के साथ कुछ समस्याएं हैं और ये किसी से छुपी नहीं है।अगर अगली सरकार इसमें सुधार करती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। नई सरकार को प्रत्यक्ष कर आधार, खासकर आयकर बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। परंतु, समस्या केवल राजस्व तक ही सीमित नहीं है। व्यय का स्तर भी बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए सरकारी समर्थन एवं सब्सिडी लक्षित लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिन लोगों को इनकी जरूरत नहीं है उन्हें लाभ पहुंच रहा है। प्रायः तात्कालिक या अल्प अवधि में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा मुरलीधरन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि वर्ष 2019-20 में पंजाब सरकार ने कृषि शोध पर 380 करोड़ रुपये की तुलना में कृषि क्षेत्र के लिए बिजली के मद में सब्सिडी पर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे। केंद्र सरकार भी इस मामले में अलग नहीं है। भारत को सबसे पहले अपनी राजकोषीय प्राथमिकता को ठीक करना चाहिए।

यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि भारत के पास अपने मानव संसाधन का लाभ उठाने की सीमित गुंजाइश मौजूद है, मगर शिक्षा में सुधार के बिना यह संभव नहीं है। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। उक्त पुस्तक में एक शोध का जिक्र किया गया है जिसके अनुसार केवल व्यय बढ़ाने से लाभ नहीं मिल सकता है। अन्य बातों में पर्यवेक्षकों के पदों पर भर्ती से पढ़ाई-लिखाई के श्रेष्ठ परिणाम सामने आ सकते हैं। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की भर्ती से कम खर्च पर बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में उम्मीद से कम परिणाम का कारण यह है कि राजकोषीय शक्ति का केंद्रीकरण आवश्यकता से अधिक है। भारत को सबसे कम विकेंद्रीकृत देशों में एक माना जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का राजस्व व्यय सभी राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.6 फीसदी से कम था। एक अध्ययन के अनुसार चीन में स्थानीय सरकारों का व्यय कुल व्यय का 51 फीसदी था जबकि भारत के मामले में यह मात्र 3 फीसदी था। कुछ खास कार्यों के लिए स्थानीय इकाइयों को तैयार करने से सरकार की क्षमता और इससे मिलने वाले परिणाम सुधर सकते हैं। स्थानीय निकायों के लिए विकास कार्यों के बेहतर परिणाम नहीं मिलने की स्थिति में स्थानीय नेताओं को उत्तरदायी ठहराना आसान हो जाएगा। अधिकारियों एवं मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की तुलना में ऐसा करना अधिक आसान होगा। लिहाजा, भारत को स्थानीय निकायों की क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है और इसका फायदा उठाकर बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंत में, न्यायपालिका की स्थिति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में इस समय 5 करोड़ मामले विचाराधीन हैं। कुछ मामलों में त्वरित न्यायालय स्थापित करने पड़ते हैं। मगर स्थापित क्षमता में कमी और कुछ मामलों के निपटारे के लिए उपाय करने से शेष क्षमता पर असर हो सकता है। मामले विचाराधीन रहने से निवेश का माहौल बिगड़ता है और अधिकारी अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने लगते हैं। न्यायालयों में मामले के जल्द निपटारे से निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस तरह, विकास की संपूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी। संक्षेप में कहें तो सरकार की क्षमता में सुधार का विचार कोई नई बात नहीं है, मगर अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में नई शुरुआत करें।

आपका पक्ष

वैश्विक व्यवधान में व्यापार और समाधान

संपादकीय 'तैयार रहने की जरूरत' इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध, लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक, स्वेज नहर में आवागमन की बाधाएं, पश्चिम एशिया में खून-खराबे के चलते वैश्विक व्यापार में अवरोधों, आर्थिक और व्यापार में गिरावट, विशेषकर भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पर गहन चर्चा करता है। यह प्रतिकूल प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों पर भी यह विपरीत असर डाल रहा है। इसमें सबसे अधिक वही देश हैं जो अनाज, दवाओं, मशीनरी, रसायन, वस्त्र, पेट्रोलियम के आयात पर सबसे अधिक निर्भर हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के पास इन कठिन परिस्थितियों पर चिंता करने और रिपोर्ट जारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे अवरोधों के सामने द्विपक्षीय या मुक्त व्यापार समझौते, विश्व व्यापार संगठन के नियम-कानून और समझौते निरर्थक हैं। अमेरिका अपने पड़ोसी उत्तरी और दक्षिणी अमरीकी देशों से वैश्विक व्यापार की भरपाई नहीं कर सकता क्योंकि उन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है। भारत के वैश्विक व्यापार की भरपाई तो काफी हद तक तकनीक, सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से संभव है परंतु भारत की भी आयात और निर्यात की आवश्यकताएं हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के आतंक और स्वेज नहर की आवागमन की समस्याओं, रूस-यूक्रेन, पश्चिमी एशिया के युद्धों के चलते भारत, रूस, ताइवान, जापान और चीन के बीच व्यापार आपसी मतभेदों के बावजूद आसान है और इन देशों के लिए लाभदायक भी। एशियाई देशों में स्थिति फिर भी शांत है और आपसी व्यापार से अपनी आयात और निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

हूती विद्रोहियों द्वारा पनामा के एक जहाज पर हमले के बाद चालक दल में शामिल रहे 22 भारतीय रविवार को देश लौटे

उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता की जरूरत

देश में इन दिनों कई कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार- प्रसार हेतु भ्रामक विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं। अगर उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी संबंधी विज्ञापन दिए जाएं तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है। आजकल दूरदर्शन पर कुछ इसी प्रकार के विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं, जहां उपभोक्ताओं को यह समझाया जा रहा है कि आईएसआई मार्क वस्तुएं खरीदना बेहतर होता है। अतः वे आईएसआई मार्क वस्तुएं ही खरीदें। दूसरी ओर वास्तविकता ये है कि कई वस्तुओं के लिए सरकार ने आईएसआई मार्क अनिवार्य किया हुआ है, मगर बाजार में बिना आईएसआई मार्क के उत्पाद भरे पड़े हैं और इनके निर्माताओं और विक्रेताओं को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तीसरे, बाजार में बहुत-सा ऐसा सामान होता है जिस पर नकली आईएसआई मार्क लगा होता है परंतु विक्रेता उसे असली बताकर उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता वाले विज्ञापनों के इस्तेमाल को और अधिक बढ़ावा मिले तो उपभोक्ता जागरूक होकर स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाएगा।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

गुजरात में पोरबंदर के पास भारतीय तट रक्षक के जवानों ने भारतीय समुद्री सीमा में रविवार को एक पाकिस्तानी नौका से अवैध रूप से भारी मात्रा में भारत लाए जा रहे ड्रग्स को जब्त किया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 29 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

सत्य सबसे प्रबल तर्क होता है

कांग्रेस में असंतोष

लोकसभा चुनावों की घोषणा के पहले से ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला कायम हुआ था, वह थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करने वालों में नया नाम जुड़ा है दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का। पता नहीं उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली में टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस के एक और नेता राजकुमार चौहान पार्टी छोड़ चुके हैं। इसकी गिनती करना कठिन है कि पिछले एक-डेढ़ माह में देश भर में कितने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। हैरानी नहीं कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक कुछ और नेता कांग्रेस छोड़ दें। पता नहीं कांग्रेस को इसकी कोई परवाह है या नहीं कि देश भर में उसके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यानी कांग्रेस नेतृत्व की नाक के नीचे जो असंतोष उभरा, उसके लिए वही जिम्मेदार है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे का एक कारण आम आदमी पार्टी से समझौता किया जाना बताया है। इस कारण की केवल इसलिए अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, क्योंकि यह एक तथ्य है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हाशिये पर ले जाने का काम आम आदमी पार्टी ने ही किया। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने अपने स्थानीय नेताओं-कार्यकर्ताओं और जमीनी हकीकत की अनदेखी कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह फैसला इसके बावजूद किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में उसके साथ मिलकर लड़ना स्वीकार नहीं किया। साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के समक्ष पूरी तरह समर्पण कर दिया। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि उसे दिल्ली की सात में से केवल तीन सीटों पर लड़ने का अवसर मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसे स्वीकार करना इसलिए कठिन रहा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी दिल्ली में पांच सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे।

अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी का एक कारण प्रत्याशी चयन भी नजर आता है। कांग्रेस ने जिस तरह अपने पुराने नेताओं की अनदेखी कर दूसरे दलों से आए कन्हैया कुमार और उदित राज को चुनाव मैदान में उतारा, उससे स्थानीय नेताओं में असंतोष उभरना स्वाभाविक था। कहना कठिन है कि इस असंतोष की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह एक तरह का राजनीतिक आत्मघात ही है कि जिस दल ने दिल्ली में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया, उससे ही उसने उसकी शर्तों पर समझौता करना पसंद किया। कांग्रेस जिस तरह अपने मजबूत गढ़ों में सहयोगी दलों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ती चली जा रही है, उससे वह अपने आपको खत्म करने का ही काम कर रही है। अच्छा हो कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि फौरी राजनीतिक लाभ के लिए वह अपने दीर्घकालिक हितों पर कुठाराघात कर रहा है।

आग का बढ़ता खतरा

बिहार में आग से जान-माल के नुकसान की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो, जब आग लगने की घटना में भारी क्षति नहीं हो रही हो। यह चिंता का विषय है, जिस पर तुरंत पहल करते हुए इसकी रोकथाम के उपाय करने होंगे। बीते गुरुवार को पटना स्थित दो होटलों में भयानक आग से सात लोगों की मौत हो गई। अगले ही दिन मसौढ़ी में आग से तबाही मची। बरात में आतिशबाजी के कारण आग लगने से दरभंगा में छह लोग जान से हाथ धो बैठे। शनिवार को रोहतास में आग से एक महिला व तीन बच्चियों की मौत हो गई।

सार्वजनिक स्थलों और भवनों में आग से बचाव के लिए सुरक्षा तंत्र का नितांत अभाव है। इस संबंध में अभियान चलाया जाना चाहिए

चूल्हे से निकली चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई और चारों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये घटनाएं नहीं हों, इसका उपाय ढूंढ़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य घटनाएं फूस के घरों में हो रही हैं, जहां उसे जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है। इसके प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना होगा कि गर्मी के मौसम में चूल्हा जलाते समय ध्यान रखें। कई घटनाएं व्यवस्था की अनदेखी के कारण भी हो रही हैं। सुरक्षा मानक का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई से ही इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। शहरों में तंग गलियों में होटलों का संचालन किया जा रहा है, जहां आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटना के जिस होटल में आग लगी, उसमें बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता तक नहीं था। ऐसे दर्जनों होटल और लाज का संचालन किया जा रहा है, जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती। यह जांच का विषय है कि वे कैसे संचालित किए जा रहे हैं और इसकी अनुमति कैसे मिल गई।

विरासत कर का बेतुका विचार

विवेक देवराय

चुनावों के बीच इस प्रकार का विचार उछालने वालों की मंशा वास्तविक आर्थिक सुधारों के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने की अधिक लगती है

आदित्य सिन्हा

अवधेश राजपूत

स्वतंत्रता के बाद से भारत में समाजवादी सोच के चलते संपदा सृजन को एक समस्या के रूप में देखा गया। समय-समय पर विशेष रूप से चुनावों के दौरान संपदा सृजन को नियंत्रित किए जाने के विचार सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में विरासत कर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ी है। यह स्थिति तब है जब संपदा सृजन को आर्थिक वृद्धि एवं नवाचार का उत्प्रेरक माना जाता है, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। इसलिए उसे गलत रूप में पेशकर भयादोहन नहीं किया जाना चाहिए। जब व्यक्तिगत एवं संस्थागत दायरे में संपदा सृजन होता है तो उसके पुनर्निवेश से रोजगार सृजन एवं तकनीकी प्रगति की राह खुलती है। इस चक्र से नए उद्योगों की वृद्धि, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और ऊंचे कर राजस्व के जरिये बेहतर सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। संपदा सृजन के माध्यम से ही निम्न-आय पृष्ठभूमि के लोगों के लिए ऊंचे वेतन वाली नौकरियों की राह खुलती है तो उद्यमियों को शैक्षणिक गतिविधियों एवं सामुदायिक परियोजनाओं में निवेश के लिए बढ़ावा मिलता है। स्थानीय विकास और सशक्तीकरण से उपलब्धियों व उद्यमिता की प्रगतिशील संस्कृति का भी विकास होता है।

समय के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक प्रगति की है और इस प्रक्रिया में कुछ विषमता की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए गाहे-बगाहे विरासत कर का सुझाव दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि मध्य वर्ग और गरीबों के उत्थान के लिए लाई जाने वाली ऐसी नीतियां अंततः उनका अहित ही करती हैं। ऐसे कदमों से जनजीवन अस्तव्यस्त होता है और आर्थिक अक्षमता बढ़ सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि चुनावों के बीच इस प्रकार का विचार उछालने वालों की मंशा वास्तविक आर्थिक सुधारों के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने की अधिक लगती है। वैसे भी विरासत कर का विचार भारत में नया नहीं है। आजादी के बाद से ही भारत में इसी प्रकार की एस्टेट ड्यूटी लागू हुई, जिसे मार्च 1985 में हटाना पड़ा। इसे हटाने के पीछे यही वजह बताई गई कि इससे राजस्व की तो बहुत कम प्राप्ति हुई, लेकिन यह एक बड़ी संख्या में करदाताओं के उत्पीड़न का कारण बना। यह ड्यूटी कम से कम एक लाख रुपये हैसियत की संपत्ति पर लगाई गई थी, जिसके लिए 7.5 प्रतिशत की दर नियत थी। हालांकि 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर इसकी दर 85 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचती थी, जिसके चलते यह दांव जनता की नजरों में खटकने लगा। केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में एस्टेट टैक्स संग्रह की हिस्सेदारी भी बेहद मामूली थी। वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान एस्टेट ड्यूटी के तहत कुल 20 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। चूंकि इस कर के आकलन की प्रक्रिया खासी जटिल थी और उसमें तमाम मुकदमेबाजी के पेच भी फंस जाते थे तो इसकी वसूली सरकार को खासी महंगी पड़ती थी। जिस समय यह ड्यूटी हटाई गई तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे लेकर अपने बजट भाषण में कहा, 'एस्टेट ड्यूटी से जहां केवल 20 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, वहीं इसके अनुपालन पर काफी प्रशासनिक व्यय करना पड़ा।' अंततः 16 मार्च, 1985 की अवधि के उपरांत इसकी समाप्ति की घोषणा हुई।

विरासत कर अक्सर आर्थिक अक्षमताओं को भी आमंत्रित करता है, जिसके कई मोर्चों पर अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार के कर से लोगों का आर्थिक व्यवहार बिगड़ सकता है। विरासत कर जैसी व्यवस्था में लोग बचत या निवेश से अधिक उपभोग की ओर उन्मुख हो सकते हैं। विरासत कर की अतिरिक्त लागत भी करदाताओं का मिजाज बिगाड़ती है। साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि ऊंचे एस्टेट टैक्स संपदा सृजन की राह में बाधक बनते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है। इसके विरोध में एक तर्क दोहरे कराधान का भी है, क्योंकि विरासत कर के दायरे में आने वाली परिसंपत्तियां पहले ही आयकर या पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आ चुकी होती हैं। यदि सक्षमता की दृष्टि से देखें तो ऐसे परिदृश्य में कोष की सीमांत सक्षमता लागत यानी एमईएसएफ काफी ऊंची हो सकती है। यह संकेत करता है कि जिन करों को एक बार ही अधिरोपित किया जाता है, उनसे राजस्व वसूली किफायती होती है। छोटे उद्यमों और पारिवारिक स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में विरासत कर के चलते तरलता की समस्या भी खड़ी हो जाती है। चूंकि ऐसी इकाइयों के पास वृहद कर देनदारियों की पूर्ति के लिए आवश्यक लिक्विड असेट्स का अभाव होता है तो उन्हें अपनी उत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री या उन्हें पूरी तरह भुनाने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे स्थापित उद्यमों का पूरा ढांचा बिगड़ सकता है, जिससे रोजगार और आर्थिक विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है।

ऊंचा विरासत कर पूंजी पलायन को भी गति दे सकता है। इसके चलते लोग अपनी पूंजी को वहां लगाना चाहेंगे जहां करों को लेकर अनुकूल व्यवस्था हो। इससे देश का कर दायरा सिकुड़ने के साथ ही घरेलू निवेश घट सकता है, जिससे संसाधन आवंटन की स्थिति गडबड़ा सकती है। विरासत कर के पेचीदा अनुपालन एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से भी यह फायदे से अधिक नुकसान करता है और संभावित राजस्व प्राप्ति नगण्य रह सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों के असंगठित स्वरूप वाले देश में विरासत कर को लागू करने की अपनी तमाम चुनौतियां हैं। रियल एस्टेट, ज्वैलरी और कृषि भूमि जैसी संपत्तियों की व्यापकता प्रभावी कराधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मूल्यांकन को जटिल बनाती है। विरासत कर के आकलन के लिए संपत्तियों का रिकार्ड आवश्यक है, जिसका भारत में अभाव है। आंकड़े डिजिटल भी नहीं हैं। कुल मिलाकर, जिस विषमता को दूर करने के लिए विरासत कर का विचार आगे बढ़ाया जाता है उससे जाने-अनजाने विषमता और बढ़ती ही है। धनाढ्य लोग बेहतर कर नियोजन के साथ अक्सर इस प्रकार के करों के प्रभाव को कुछ कम करने या उससे बच निकलते हैं, जबकि अपेक्षाकृत कम संसाधनसंपन्न लोगों को उसकी तपिश झेलनी पड़ती है।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता

डा. ऋतु सारस्वत

यह धारणा सही नहीं कि भारतीय महिलाएं घर के पुरुष सदस्यों के सोच के अनुरूप मतदान करती हैं

अपने हितों के प्रति सचेत हैं महिलाएं। फाइल

आम चुनाव के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु इसमें किंचित संदेह नहीं कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में उभर आई हैं और यह सुखद आश्चर्य है कि अब वे पुरुष मतदाताओं से एक कदम आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। दुनिया भर के अध्ययन इस अवधारणा को स्थापित करते आए हैं कि 'सामाजिक-आर्थिक समानता महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लेकर जाती है।' साफ है कि भारत बहुत हद तक लैंगिक असमानता की खाई को पाट चुका है, क्योंकि मतदान केंद्रों तक वे महिलाएं नहीं पहुंच सकतीं, जिनमें आत्म-सशक्तीकरण का अभाव हो। आत्म-सशक्तीकरण का प्रत्यक्ष संबंध लैंगिक समानता से है। भारतीय महिलाएं सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरेंगी, यह आकलन आइरिश टाइम्स ने पहले आम चुनाव के समय ही कर दिया था। तीन दिसंबर, 1951 को 'इंडियन इलेक्शन कुड बी हाउसवाइव्स च्वाइस' शीर्षक से लिखे लेख के अनुसार 'चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले दल घोषणा पत्रों और उम्मीदवारों के चयन में गृहिणियों को खुश रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।'

आज तो कोई भी दल महिला मतदाताओं की अनदेखी का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि वे जान चुके हैं कि चाहे बात निरक्षर महिला की हो या उच्च शिक्षित की, चाहे प्रश्न ग्रामीण घरेलू महिला का हो या फिर नौकरीपेशा शहरी महिला का, वे भलीभांति जानती हैं कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना है? जो भी दल उनकी पीड़ा को समझेगा या उनके हितों को साधेगा, उनका वोट उसे ही जाएगा। इस तथ्य की पुष्टि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों से हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले शराबबंदी से जुड़ी महिलाओं की मांग पर कहा था कि अगर इस बार हमारी सरकार बनी तो हम शराब बंद करेंगे। इस वादे के बाद हुए चुनावों में जदयू की भागीदारी वाले महागठबंधन ने 178 सीटें जीतीं। करीब 60.57 प्रतिशत महिलाओं ने अपने घरों से निकल कर वोट दिया, जो पुरुषों के मुकाबले करीब सात प्रतिशत ज्यादा था। महिलाओं के हितों को साधने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रहीं। महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मुआवजे में वृद्धि, साइकिल योजना जैसी नीतियों ने उन्हें महिला समर्थक के रूप में अपनी छवि बनाने में काफी मदद की। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में 'लाड़ली बहन योजना' को एक ट्रंप कार्ड के रूप में देखा गया।

महिलाएं भ्रामक भावनाओं में बहने को तैयार नहीं हैं। यह बात कोरा मिथक है कि किसी एक राजनीतिक दल की हवा उनके मन को प्रभावित कर सकती है। यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि महिलाएं उस नेता या दल का चुनाव करती हैं, जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव हो जाए और उन्हें यह भरोसा हो कि वे उनके हितैषी हैं। संभवतः अंतरराष्ट्रीय मुद्दे और बाजार के उतार-चढ़ाव आम भारतीय महिलाओं के विमर्श के विषय नहीं हैं, परंतु उनकी जमीनी जरूरतों को समझने वाला नेतृत्व उनकी प्राथमिकता में होता है। वे व्यक्तिगत और संस्थागत, दोनों स्तरों पर संचालित होने वाले अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं। पांच दशकों के राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में पुरुष और महिला मतदान के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पारंपरिक रूप से पिछड़े और अपेक्षाकृत अधिक विकसित भारतीय राज्यों, दोनों में महिला चेतना और आत्म-सशक्तीकरण की परिकल्पना का सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है। यह धारणा आंकड़ों और चुनावी परिणामों से मेल नहीं खाती कि 'भारतीय महिलाएं घर के पुरुष सदस्यों के सोच के अनुरूप मतदान करती हैं।'

विभिन्न शोधों में महिला मतदाताओं ने दबे स्वर में यह स्वीकार किया कि वे वोट देते समय अपने परिवार के निर्णय को ध्यान में नहीं रखतीं। मतदान स्वायत्तता बीते एक दशक के लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखी जा सकती है। जो महिलाएं कुछ दशक पहले तक 'मिसिंग वूमेन' मानी जाती थीं, वे अब 'महिला-इन-द-मिडिल' में सम्मिलित हो गई हैं। बेहतर शिक्षा, बढ़ती जागरूकता और आर्थिक स्वावलंबन ने आधी आबादी की निर्णय क्षमता को बल दिया है। महिलाएं बेहतर तरीके से समझ चुकी हैं कि उनके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार नित्य नवीन योजनाएं लाने को तत्पर हैं। इसके चलते उन्होंने अपने हितों को साधना सीख लिया है। भारतीय स्टेट बैंक के इकोनमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की आम चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका से जुड़ी एक रिपोर्ट यह बताती है कि स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा, पीएम जीवन ज्योति बीमा जैसी कई सरकारी योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना में उनकी चुनावी भागीदारी भी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि 2024 में मतदान का आंकड़ा 68 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें महिलाओं की संख्या 32 करोड़ हो सकती है। 2029 में 36 करोड़ पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाता 37 करोड़ हो सकती हैं।

मतदाता स्थायी रूप से कभी भी किसी एक प्रवाह में नहीं बहते, परंतु बात जब महिला वोटर की हो तो वे अपनी निष्ठा शीघ्र नहीं बदलतीं, विशेषकर तब जब बात उनकी अस्मिता और सुरक्षा की हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण हैं। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता और प्रभावकारिता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के लिए प्रदान की गई स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन का सांचा

किसी भी रूप या आकृति को ढालने के लिए सांचे की आवश्यकता होती है। किसी भी खिलौने को सांचे के बिना बनाना बड़ा कठिन कार्य है। यदि खिलौने का सांचा अच्छा होगा तो एक सुंदर खिलौना बनाया जा सकेगा। वहीं, यदि सांचा ही दोषपूर्ण हो तो एक अच्छे खिलौने को बनाए जाने की उम्मीद निरर्थक है। ठीक यही स्थिति मानव मन की है। जब मन एक सुंदर और श्रेष्ठ सांचे में ढल जाता है तो वह एक सुंदर मन बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मन उसके सांचे के अनुरूप ही ढल जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ और संतोष जैसे श्रेष्ठ सांचे में ढलकर श्रेष्ठ मन बनता है।

व्यक्ति जिन भावनाओं, विचारों का मनन अपने मन में करता है, मन उसी के अनुरूप बन जाता है। उन्हीं भावनाओं के संकल्प-विकल्प उसमें उठने लगते हैं। मन यदि भक्ति की भव्य भावनाओं का मनन करेगा तो वह भक्तिमय हो जाएगा। यदि वह ज्ञान का मनन करेगा तो ज्ञानमय और कर्म पर विचार और व्यवहार करने पर वह कर्ममय बन जाएगा। इसी प्रकार हिंसा, चोरी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम आदि भावों का चिंतन करने से मन बुरा आकार ले लेगा। वस्तुतः, मन भावों का ही रूप है। दीपावली में बनने वाले शक्कर के खिलौने की शक्कर यदि तोते के रूप वाले सांचे में ढलती है तो शक्कर तोता बन जाती है। इसमें शक्कर की अपनी कोई सत्ता नहीं है। वह अपनी इच्छा के अनुकूल कुछ भी नहीं बन सकती। वास्तव में उसे जिस सांचे का रूप मिलता है, वह उसी के अनुरूप ढल जाती है। ठीक इसी प्रकार मन जिस भी भावना के संपर्क में आता है, उसे ही धारण करता है। यही भाव जब घनीभूत हो जाते हैं तो संस्कार रूप बन जाते हैं। इस प्रकार मन की अच्छाई या बुराई उसके संग पर निर्भर करती है। श्रेष्ठ एवं शुभ भावनाओं, विचारों और व्यवहार का अभ्यास करते-करते मन स्वयं शुभ हो जाता है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

गर्मी और लू का भयावह प्रहार

चेतनादित्य आलोक

समूचे विश्व में बढ़ती गर्मी पूरी सृष्टि के लिए भयानक खतरा बनती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान है। आइएमडी के अनुसार अगले दो माह में देश के छह राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

देखा जाए तो पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्मी की शुरुआत फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन बीच-बीच में कहीं-कहीं होती थोड़ी-बहुत बारिश ने इसे हद से बाहर जाने से रोकने का कार्य किया, अन्यथा इसने मार्च में जैसा प्रचंड रूप धारण किया था, वैसा हमें फरवरी में ही देखने के लिए मिल जाता। अध्ययनों से पता चलता है कि विश्व भर में गर्म दिनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि दूसरी ओर सर्दी यानी ठंडे दिनों की संख्या घटती जा रही है। प्रत्येक नया वर्ष और अधिक गर्म होता जा रहा है।

हर नया वर्ष पिछले की तुलना में अधिक गर्म होता जा रहा है जो चिंताजनक है

आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में वर्ष 2015 को सर्वाधिक गर्म वर्ष की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि 2015 में देश के कई शहरों का तापमान 48 डिग्री तक चला गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2015 में भारत में चलने वाली लू दुनिया की सर्वाधिक खतरनाक लू की सूची में पांचवें स्थान पर थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2010 सर्वाधिक गर्म साल था, जबकि कुछ रिपोर्टों में 2019 को सबसे गर्म वर्षों में से एक माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2019 में 16 दिनों तक, 2018 में 19, 2017 में 15, वर्ष 2014 में 15 एवं वर्ष 2015 में 18 दिनों तक देश का पारा काफी ज्यादा रहा था। इस प्रकार गर्मी अपने ही बनाए पहले के रिकार्ड को तोड़ने का कार्य भी करने लगी है।

एक देशव्यापी विश्लेषण के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी को काबू करने के लिए नीतिगत तैयारी का अभाव है। हीट एक्शन प्लान के बिना हवा का बढ़ता तापमान, जमीन की सतह से निकलने वाली गर्मी, कंक्रीटिंग, औद्योगिक प्रक्रियाओं और एयर कंडीशनर से निकली गर्मी इस समस्या के कई रूप हैं। ऐसे में गर्मी से सुरक्षा प्रदान करने वाले जंगलों, शहरी हरियाली और जलाशयों के क्षरण से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मामले में समयबद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता को नकारना आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि बढ़ती गर्मी हमारी धरती, पर्यावरण और कृषि समेत हमारे जीवन के लिए भी बेहद खतरनाक है। गर्म वातावरण में अनेक प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया पनपते एवं विस्तार पाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। चिकित्सकों का भी मानना है कि निरंतर बढ़ रहा तापमान सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और कई बीमारियों को आमंत्रण भी दे रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

इतिहास को दोहराने पर आमादा कांग्रेस

'वामपंथी विचारों में जकड़ी कांग्रेस' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने कांग्रेस की मौजूदा दशा-दिशा से परिचित कराया है। उन्होंने उचित ही उल्लेख किया कि नरसिंह राव के दौर में ही भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया। आर्थिक विश्लेषक अक्सर इस बात का हवाला देते हैं कि भारत ने यदि चीन के साथ ही आर्थिक सुधारों की शुरुआत की होती तो भारत की तरक्की की कहानी कुछ अलग होती। नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का रुख कुछ पूंजीवादी विरोधी रहा। देश में उद्योगों के लिए कायम रही लाइसेंस-परमिट की व्यवस्था ने भी भारतीय उद्योग जगत की संभावनाओं को सीमित दायरे में रखा। कांग्रेस इतिहास की इन भूलों से सीख लेने के बजाय उन्हें दोहराने पर आमादा है। यह स्थिति देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाने वाली है। एक समय कांग्रेस की पहचान मध्यमार्गी दल के रूप में थी, लेकिन राहुल गांधी के दौर में वह तेजी से वामपंथी होती जा रही है। यह रवैया कांग्रेस को शायद ही कोई लाभ दे।

केशव तिवारी, आजमगढ़

आंदोलन से देश का नुकसान

पंजाब में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन से आमजन की दुश्वारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ट्रेन यात्रियों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन किसान आंदोलनकारी संगठनों द्वारा कानून हाथ में लेकर ट्रेन रोककर किया जा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। पंजाब, हरियाणा एवं

मेलबाक्स

उत्तराखंड में सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन रद किए जाने एवं रूट परिवर्तित किए जाने से यात्रियों को भारी परेशान झेलनी पड़ रही है। अभी दो दिन पहले ही एक खबर आई थी कि पंजाब में एक एक्सप्रेस ट्रेन को 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग सात घंटे लग गए। यात्रियों के टिकट रिफंड दिए जाने के कारण रेलवे के राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार किसान आंदोलनकारी संगठनों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं। किसान संगठनों का उद्देश्य देश एवं प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाए रखना प्रतीत हो रहा है। बेहतर हो कि सरकारी प्रतिनिधि किसान संगठनों के साथ सार्थक वार्तालाप के माध्यम से आंदोलन समाप्ति पर जोर दें। आंदोलन से देश का नुकसान हो रहा है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

बदहाल कांग्रेस

एक जमाना था जब देश के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि गठबंधन के बिना कांग्रेस का अस्तित्व शून्य के समान होता जा रहा है। आपातकाल के बाद से 1984 के चुनाव को छोड़ दें, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए थे, तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण गांधी परिवार की नीतियां हैं। मुख्यतः राहुल गांधी की अपरिपक्वता, अनुभवहीनता के अतिरिक्त उनकी अभद्र एवं अमर्यादित भाषा के कारण अधिकतर पार्टी नेता असंतुष्ट होकर बारी-बारी से हाथ झटक रहे हैं। हाल ही में कई प्रभावशाली नेताओं का कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने से विपक्षी घटक दलों को शर्मनाक झटका लगा है। देश के अनुभवी राजनीतिज्ञों की मानें तो कांग्रेस के अतिरिक्त द्रमुक और वामपंथियों की सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी आइएनडीआइए को भारी पड़ सकती है। तमाम टिप्पणीकारों के अनुसार, राहुल गांधी का वामपंथियों के प्रति अधिक आकर्षण होने से पार्टी कार्यकर्ता असंतुष्ट दिख रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की ताजपोशी तो दूर की बात, अब कांग्रेस लाचार दिखती है। मोदी सरकार की उपलब्धियों तथा सफल कूटनीति, कटिबद्ध नैतिकता और बेदाग नियति को देखते हुए जन समुदाय का जनादेश इस बात का साक्षी है। अधिकांश लोगों का कहना है कि अबकी बार कांग्रेस सत्ता में नहीं आती तो बेहतर है राहुल गांधी को संन्यास ले लेना चाहिए।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अकेलापन और अवांछित होने का एहसास सबसे भयानक गरीबी है। -मदर टेरेसा

क्रिसिल की आशंका वाकई चिंतनीय है कि अगले कुछ महीनों तक सब्जियों की बढ़ी कीमतों से राहत नहीं मिलने वाली। इसके लिए मौसमी घटनाओं के साथ भंडारण की सुदृढ़ व्यवस्था का अभाव भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन फसलों के नुकसानों को कम कर महंगाई पर कुछ काबू तो पाया ही जा सकता है।

महंगी होती थाली

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की यह आशंका कि समग्र महंगाई के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जियों की बढ़ी कीमतों से आने वाले कुछ महीनों तक राहत नहीं मिलेगी, आम आदमी की परेशानियों को बढ़ाने वाली है, जाहिर है कि थाली अभी महंगी बनी रहेगी। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि 2023-24 में खाद्य महंगाई बढ़ाने में सब्जियों का योगदान करीब तीस फीसदी रहा, जो उनकी सामान्य हिस्सेदारी 15.5 फीसदी से लगभग दोगुना था। दरअसल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पहले ही जून तक तापमान के सामान्य से ऊपर रहने की भविष्यवाणी कर चुका है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक की ताजा बुलेटिन में भी चरम मौसमी घटनाओं और भू-राजनीतिक तनावों के चलते कच्चे तेल की कीमतों के अस्थिर होने और मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका जताई गई थी। दरअसल, इस वित्त वर्ष में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम तो था ही, इसका वितरण भी असमान था, जो असामान्य रूप से शुष्क था। इसके बावजूद, महंगाई कोई नई घटना नहीं है। इस मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ती ही हैं। पर इस बार मौसम के अनियमित पैटर्न जिस तरह से उत्पादकों व उपभोक्ताओं के लिए चिंताएं बढ़ा रहे हैं, उससे सब्जियों की कीमतें खासी प्रभावित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में सब्जियों की कुल खपत में आलू, टमाटर और प्याज का एक-तिहाई हिस्सा होता है। इन तीनों की कीमतों में थोड़ा भी फर्क आता है, तो कीमतें प्रभावित होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर, 2020 से 23 के बीच के वित्तीय वर्षों में उससे पहले के चार वित्तीय वर्षों की तुलना में सब्जियों की कीमतों में जो 5.7 फीसदी की वृद्धि हुई, उसका मुख्य कारण था कि इन तीन सब्जियों के दाम में 9.1 फीसदी की वृद्धि। वर्ष 2023-24 में भी खुदरा बाजार में आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में एक वर्ष के भीतर 42 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी तस्दीक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े भी करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सब्जियों का मूल्य

बाजार में उनकी उपलब्धता पर निर्भर है, पर मौसमी बदलाव, ओलावृष्टि और कीटों की समस्या के चलते फसलें बाजार तक कम पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा, एक बड़ी समस्या देश में सब्जियों के भंडारण की सुदृढ़ व्यवस्था न होने से भी जुड़ी है। ज्यादातर शीतगृह असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें सुविधाएं तो परंपरागत स्तर की हैं ही, वितरण भी असमान है। वैश्विक तापमान को रोकने में भले ही हमारी सीमाएं हों, लेकिन फसल के नुकसानों को कम कर महंगाई पर कुछ काबू पाने के लिए हम संरचनात्मक समाधान तो तलाश ही सकते हैं।

इस्राइल हमेशा युद्ध नहीं लड़ सकता

हमास से प्रतिशोध लेने के लिए इस्राइल ने जो कदम उठाए, वे स्वाभाविक थे। पर वह हमेशा युद्ध नहीं लड़ सकता। इस्राइल के रुख से आईएस व अल कायदा में भर्तियां तेज हुई हैं, दुनिया में उसके खिलाफ माहौल बना है, जिससे ईरान खुश है। राफा को नष्ट करके इस्राइल वही गलती करेगा, जो इराक में अमेरिका ने की थी।

अमेरिकी कूटनीति ने गाजा युद्ध को समाप्त करने और सऊदी अरब के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए इस्राइल एवं उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक विकल्प पेश किया कि आपको क्या चाहिए- राफा या रियाद। यदि आप हमास को खत्म करने के लिए राफा पर बड़ा हमला करना चाहते हैं, तो गाजा से निकास की रणनीति या गैर-हमास नेतृत्व वाले फलस्तीन के साथ द्वि-राष्ट्र समाधान के बिना क्या यह संभव है? यदि आप इस रास्ते पर बढ़ते हैं, तो यह केवल इस्राइल के वैश्विक अलगाव को बढ़ाएगा और बाइडन प्रशासन के साथ दरार पैदा करेगा। या, यदि इस्राइल गाजा में अरब शांति सेना की तैनाती और अमेरिकी नेतृत्व में ईरान के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाकर मुस्लिम देशों से रिश्तों को सामान्य बनाना चाहता है, तो नेतन्याहू सरकार को पुनर्निर्मित फलस्तीन प्राधिकरण के साथ फलस्तीनी मुल्क की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

थॉमस एल. फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

जो बात मुझे परेशान करने वाली एवं निराशाजनक लगती है, वह यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन, विपक्ष या सेना में आज कोई प्रमुख इस्राइली नेता नहीं है, जो इस्राइलियों को यह समझा सके कि उसे राफा पर हमले के बजाय क्यों सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य बनाने का दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। आश्चर्य की बात नहीं कि पिछले वर्ष सात अक्तूबर को हमास द्वारा की गई क्रूरतापूर्ण हत्याओं, बलात्कार और अपहरण से सदमे में पड़े इस्राइली स्वाभाविक ही बदला लेना चाहते हैं और वे इतने कठोर हो चुके हैं कि उन्हें गाजा में मारे जा रहे नागरिकों, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं, की परवाह नहीं है। हमास द्वारा बचे हुए बंधकों की रिहाई से इन्कार करने से यह कठोरता और बढ़ गई है।

लेकिन बदला लेना कोई रणनीति नहीं है। यह पूरी तरह पागलपन है कि छह महीने से युद्ध करने के बावजूद इस्राइली सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक वर्ग ने नेतन्याहू को 'पूर्ण विजय' तक इसे जारी रखने को

कहा है, जिसमें शायद बिना किसी निकास योजना के राफा में युद्ध में उतरना भी शामिल है। यदि इस्राइल गाजा और वेस्ट बैंक, दोनों पर स्थायी रूप से कब्जा कर लेता है, तो यह एक विषाक्त सैन्य, आर्थिक और नैतिक ज्यादती होगी, जिससे ईरान खुश होगा और पश्चिम एवं अरब जगत में उसके सारे सहयोगी पीछे हट जाएंगे।

रियाद और वाशिंगटन में लोगों से हुई बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि गाजा पर इस्राइली हमले के बारे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नजरिया कुछ इस प्रकार है-जितनी जल्दी हो सके, इस्राइल को गाजा से बाहर निकलना चाहिए, गाजा में इस्राइल द्वारा नागरिकों की हत्या से सऊदी अरब के वैसे लोग भी इस्राइल के खिलाफ हो गए हैं, जो रिश्ते को सामान्य बनाना चाहते थे। इससे अल कायदा एवं आईएस में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां शुरू हो गई हैं, जो ईरान तथा उसके सहयोगी को मजबूत बना रहे हैं। इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है और सबसे जरूरी विदेशी निवेश घट रहा है। सऊदी अरब की नजर में हमास को खत्म कर देने का विचार कोरा स्वप्न है।

यदि इस्राइल गाजा का नेतृत्व करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी सेना हमेशा युद्ध नहीं लड़ सकती। इसलिए इस्राइल को जितनी जल्दी हो सके, पूर्ण संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर ध्यान देना चाहिए और अमेरिकी-सऊदी-इस्राइल-फलस्तीनी सुरक्षा-सामान्यीकरण समझौते पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा रास्ता है, जिसे इस्राइल अभी अपना सकता है। हालांकि इस्राइल का कोई भी विपक्षी नेता इसे शीर्ष प्राथमिकता में नहीं रखता, लेकिन बाइडन प्रशासन, सऊदी, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को एवं अमीरात के लोग इसके समर्थक हैं। इसकी सफलता निश्चित नहीं है, और न ही वह 'संपूर्ण जीत' है, जिसका वादा नेतन्याहू कर रहे हैं। यह दूसरा रास्ता राफा पर इस्राइल द्वारा पूर्ण सैन्य आक्रमण का विचार छोड़ने से शुरू होता है, जो गाजा में पहुंचने वाले मानवीय सहायता ट्रकों के गुजरने का मुख्य मार्ग है। यह दो लाख स्थायी निवासियों का घर है और अभी वहां उत्तरी गाजा से गए दस लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। बाइडन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू को कहा है कि उन्हें दस लाख से अधिक नागरिकों को हटाने की ठोस योजना के बिना वहां पूर्ण आक्रमण नहीं करना चाहिए, और इस्राइल ने अब तक ऐसी कोई योजना पेश नहीं की है। निजी तौर पर बाइडन प्रशासन ने कहा है कि राफा पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं होगा।

एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बाइडन की टीम हमास के आकाओं को बख्शना नहीं चाहती है, केवल गाजा को बड़े पैमाने पर नागरिक क्षति से बचाना चाहती है। वे कहते हैं कि अगर खान यूनिस एवं गाजा को नष्ट करने के बाद इस्राइल राफा को नष्ट कर देता है, तो युद्ध जर्जर गाजा पर शासन के सुरक्षा बोझ से राहत दिलाने के लिए उसके पास कोई फलस्तीन साझेदार नहीं होगा। यह वैसी ही गलती होगी, जैसी इराक में अमेरिका ने की थी। अंततः उसे मानवीय संकट के शीर्ष पर स्थायी विद्रोह से निपटना होगा। लेकिन दोनों में अंतर है और इस्राइल महाशक्ति नहीं है। अगर बाइडन प्रशासन की आपत्तियों के बावजूद इस्राइल राफा में सैन्य अभियान चलाता है, तो अमेरिका उसे हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है।

बाइडन की टीम चाहती है कि अमेरिका और सऊदी इस्राइल में विपक्ष की भूमिका निभाए, जो नेतन्याहू को कह सके कि क्या वह ऐसे नेता के रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, जिसके शासन में सात अक्तूबर जैसी सबसे बुरी सैन्य तबाही हुई या फिर ऐसे नेता के रूप में, जिसने इस्राइल को गाजा से बाहर निकाला और इस्राइल एवं महत्वपूर्ण मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। चुनाव उन्हें करना है। और अमेरिका इस विकल्प को सार्वजनिक रूप से पेश करना चाहता है, ताकि सभी इस्राइल वासी देख सकें। जाहिर है, रियाद के साथ बेहतर रिश्ते बनाना इस्राइल के दीर्घकालीन हित में है, राफा पर आक्रमण करना नहीं। बेशक कुछ भी निश्चित नहीं है और दोनों विकल्पों में जोखिम हो सकता है। बेशक इस्राइलियों के लिए यह आकलन करना आसान नहीं है, लेकिन राफा पर हमला करने की तुलना में अंततः रियाद के साथ जाने से इस्राइल को ज्यादा फायदा होगा।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

चिदानंद सरस्वती

जिस मनुष्य का हृदय मलिन है, उसमें ज्ञानाग्नि जलाने में अधिक समय लगता है। जिसका हृदय शुद्ध है, वह पल भर में ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

हृदय शुद्ध है, परेशानियां क्या बिगाड़ लेंगी

जब घर में आग लगी हो, तब आप कितने साहस के साथ घर में घुसकर सोए हुए बच्चे को उठा लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी आपको साहसी होना चाहिए। आपको शरीर से जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी आप शीघ्र आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। कायर लोग आध्यात्मिक मार्ग के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। यदि किसी बड़े वृक्ष के ऊपर आम लगे हों, तो आप एक ही छलांग लगाकर उसे नहीं तोड़ पाते। आप कई शाखाओं को पकड़ते हुए वृक्ष पर धीरे-धीरे चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आप एक ही छलांग में आध्यात्मिक साधना के शीर्ष पर नहीं चढ़ सकते। आपको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। आपको यम-नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का अभ्यास करना होगा। तभी आप योग की सबसे ऊंची सीढ़ी-समाधि को प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप वेदांत के साधक हैं, तो पहले साधन चतुष्टय से संपन्न हो लीजिए, तब आपको श्रवण-मनन और ध्यान करना होगा। तभी आप ब्रह्म साक्षात्कार कर सकेंगे।

यदि आप भक्तियोग के साधक हैं, तो आपको श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सखा और आत्मनिवेदन का अभ्यास करना होगा। तभी आप पराभक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।

यह मन हमेशा पांच प्रकार के विषयों के उपभोग के लिए दौड़ता है। उसमें धीरे-धीरे जप और ध्यान के अभ्यास से आध्यात्मिक सुख के आस्वादन की आदत डालिए। जीवन्मुक्त अथवा भागवत की आंखें चमकीली होती हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं, उनकी छाप आपके मन के ऊपर अमिट रहती है। उनमें असीम आकर्षण शक्ति होती है। वे आपकी सारी शंकाओं को जादू की तरह भगा देते हैं। उनके सामीप्य में आप विशिष्ट आनंद और शांति का अनुभव करेंगे, तो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। वे बहुत ही कारुणिक होते हैं। वे स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार, काम तथा अभिमान से मुक्त होते हैं। वे सत्य, शांति, ज्ञान और सुख की प्रतिमूर्ति होते हैं।

जिस मनुष्य का हृदय मलिन है, उसमें ज्ञानाग्नि जलाने में अधिक समय लगता है। जिसका हृदय शुद्ध है, वह पल भर में ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिनमें शुद्धता, नम्रता, प्रेम, भक्ति, वैराग्य और विचार हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती। वे आसानी से निकलकर अमृतत्व के धाम को प्राप्त करते हैं। साधारण कागज के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं। आप इसे फेंक देते हैं। परंतु जब वह मुद्रा होती है, तो आप उसे अपनी थैली में संभाल कर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार पत्थर के साधारण टुकड़े का कोई मोल नहीं है, पर यदि आप किसी मंदिर में ईश्वर की प्रस्तर मूर्ति को देखते हैं, तो आप सिर झुका कर पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की मुहर लगी है। सुख उससे भी मिलता है, पर कायरता वहां भी नहीं चल सकती।

अध्यात्म का महत्व...

सूत्र

मनुष्य का मूल अध्यात्म हैं। परमात्मा व उनकी मूर्ति में श्रद्धा, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास, सम्मान, बड़े व गुरुजनों के प्रति आदर-सत्कार आदि यह सब संस्कार अध्यात्म से बचपन में ही प्राप्त हो जाते हैं। अध्यात्म से बहुत कुछ सीखते हैं। इंसान चाहे कैसा भी जीवन जी रहा हो, उसे अध्यात्म का सहारा मिल जाए, तो जीवन की यात्रा सुगम व सरल हो जाती है।

दूसरा पहलू

दुनिया में हर पंद्रहवें दिन एक भाषा मर रही है, वहीं भारत में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्फत इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।

भाषाओं को बचाने की भारतीय पहल

कोई भी भाषा जब मातृभाषा नहीं रह जाती, तो उसके प्रयोग की अनिवार्यता में कमी आने से रोजगार मूलक कार्यों में भी कमी आने लगती है। पिछले 75 सालों में हमारी भाषाओं और बोलियों के साथ यही होता रहा है, परंतु अब नई 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (एनईपी) लागू करने की पहल करते हुए केंद्र सरकार नए सत्र से पांच नए उपाय करने जा रही है। इनमें बच्चों को मातृ, घरेलू और क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पहले चरण में 17 राज्यों की राजभाषा व स्थानीय भाषा में 52 पुस्तकें मैसूर के 'भारतीय भाषा संस्थान' और 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद' (एनसीईआरटी) ने तैयार की हैं। देश में ऐसी 121 भाषाएं हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर लिखा व बोला जाता है।

प्रमोद भार्गव

पूरी दुनिया में 15 हजार से अधिक भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन आज उनमें से आधी से ज्यादा मर गई हैं। अभी विश्व की 90 प्रतिशत भाषाओं-बोलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।

संकटग्रस्त भाषाओं में असम की 17 भाषाएं शामिल हैं। सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को आज बांचने वाला कोई नहीं है। 52 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई एक अनूठी पहल है।

26 जनवरी, 2010 को अंडमान द्वीप समूह की 85 वर्षीय बोआ के निधन के साथ ग्रेट-अंडमानी भाषा 'बो' भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। इसके पूर्व नवंबर, 2009 में एक और महिला बोरो की मौत के साथ 'खोरा' भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 'नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ऐंड लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेज' के अनुसार, हरेक पखवाड़े एक भाषा की मौत हो रही है। वर्ष 2100 तक भू-मंडल में बोली जाने वाली सात हजार से भी अधिक भाषाओं का लोप हो सकता है।

भारत सरकार ने उन भाषाओं के आंकड़ों का संग्रह किया है, जिन्हें दस हजार से अधिक लोग बोलते हैं। पूरी दुनिया में सत्ताईस सौ भाषाएं संकटग्रस्त हैं। इन भाषाओं में असम की 17 भाषाएं शामिल हैं। 'यूनेस्को' द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, असम की देवरी, मिसिंग, कछारी, बेइटे, तिवा और कोच राजवंशी सबसे संकटग्रस्त भाषाएं हैं। वे ही भाषाएं बोलियों और लिपियों के रूप में जीवित रह सकती हैं, जो उपयोग में बनी रहें। पूरी दुनिया में 15 हजार से अधिक भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन आज उनमें से आधी से ज्यादा मर गई हैं। अभी विश्व की 90 प्रतिशत भाषाओं-बोलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। भारत की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को आज बांचने वाला कोई नहीं है।

भाषाओं को बचाने के लिए जरूरी है कि स्थानीय भाषा के जानकारों को ही रोजगार दिए जाएं। इससे भारतीय भाषाओं के संरक्षण के साथ अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी और ये लोग अपनी भाषा को गरिमा भी प्रदान करेंगे। इस नजरिये से 52 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई एक अनूठी और आवश्यक पहल है। (सप्रेस)

आंकड़े

नींद के घंटे

सबसे ज्यादा (औसतन सात घंटे) न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के लोग रात में सोते हैं। भारत में लोग औसतन 6.4 घंटे की नींद लेते हैं।

देश	घंटे
न्यूजीलैंड	7.0
ऑस्ट्रेलिया	7.0
रूस/ब्रिटेन	6.9
अमेरिका	6.9
भारत	6.4

आंकड़े घंटे में | स्रोत : Economist; Oura Ring

अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो दूसरों का ख्याल रखता है, वही दुनिया को कुछ नया दे सकता है।

जीवन की बारीक समझ

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार स्वामी विवेकानंद को अमेरिका से एक सेमिनार में बोलने के लिए बुलाया गया। जब उनकी मां को यह बात पता चली, तो उन्होंने विवेकानंद को सूचना भिजवाई कि वह जांचना चाहती हैं कि विवेकानंद विदेश में बोलने लायक हुए हैं या नहीं। मां के आदेश पर स्वामी जी घर पहुंचे। मां ने उन्हें खाना दिया, जिसे स्वामी जी ने स्वाद लेकर खाया। फिर मां ने उन्हें एक सेब एवं चाकू देकर फल खाने को कहा। स्वामी जी ने काटकर सेब खा लिया। फिर मां ने उनसे चाकू मांगा। स्वामी जी ने मां को चाकू दे दिया।

मां ने कहा, अब मैं आश्वस्त हूं कि तुम विदेश जाकर लोगों को ज्ञान देने के लायक हो गए हो। स्वामी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह आश्चर्य से बोले, लेकिन मां, तुमने मेरी कोई परीक्षा तो ली ही नहीं।

मां बोली, बेटा, अभी मैंने तुमसे चाकू मांगा, तुमने धार की ओर से इस तेज चाकू को पकड़कर इसका लकड़ी वाला हिस्सा मेरे सामने कर दिया, ताकि मैं इसे आराम से पकड़ सकूं। तुमने यह नहीं सोचा कि तेज धार से तुम्हें भी चोट लग सकती थी। इसलिए तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ, देश-दुनिया में अपने ज्ञान का प्रसार करो। यह बात सुनकर स्वामी जी का सिर मां के सामने श्रद्धा से झुक गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 नवंबर, 1990

आरक्षण नीति के विरोध में आत्मदाह की कोशिश

जबलपुर में छात्र द्वारा आत्मदाह की कोशिश

आरक्षण नीति के विरोध में जबलपुर के 12वीं कक्षा के एक छात्र मनीष नरुला ने आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, 70 प्रतिशत तक जले उस छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

कटु यथार्थ के भुक्तभोगी फुले-आंबेडकर

डॉ. आंबेडकर ने फुले से विद्या और सामाजिक सम्मान सीखा, शिक्षा को जाति-धर्म के भेदों से मुक्त कर उसे शुद्ध मानवीय बनाया।

श्यौराज सिंह 'बेचैन'

स्मरण

महात्मा फुले की कहानी एक भुक्तभोगी समाज सुधारक की कहानी है, जो अप्रैल में ही चौंसठ साल बाद पैदा हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर की कहानी की पूर्व पीठिका है। फुले 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में जातिभेद के कारण अपमानित हुए थे। फुले की मृत्यु 1890 में हुई और ठीक एक साल बाद पैदा हुए आंबेडकर को भी जाति भेद, अस्पृश्यता अपने विकराल रूप में सक्रिय होती मिली। वह स्कूल गए, तो 'उच्च जाति के हिंदू बच्चों' ने साथ बैठने से मना कर दिया। अध्यापक ने कक्षा के बाहर बैठ कर पढ़ने की इजाजत दी। कैशियर की नौकरी कर रहे पिता से मिलने गए, तो स्टेशन से सवारी नहीं मिली। स्वयं हांक कर ले जाने की शर्त पर बैलगाड़ी मिली, तो समय पर पहुंच नहीं पाए। बड़ौदरा नरेश के राज्य में वित्त-सचिव बने, तो किराये का मकान नहीं मिला। धर्म/जाति छिपा कर रहे, तो उन्हें बलपूर्वक बाहर निकाला गया। ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यों के लिए जल-

कुएं खुलवा दिए। वर्ष 1848 से ही बालिका विद्यालय खोलने की शुरुआत की, और मुंबई प्रेसिडेंसी में मुस्लिम और अस्पृश्य बच्चों के लिए कुल 18 विद्यालय खोलने का रिकॉर्ड बनाया।

वर्ष 1873 में 'सत्य शोधक समाज' का गठन कर, फुले दंपती ने समाज सुधार की रचनात्मक मुहिम छेड़ी। 'अस्पृश्यता' और 'जाति भेद' के खिलाफ समाज में आत्मसम्मान की चेतना जागृत की। फुले पर तुकाराम चोखामेला, कबीरवाणी और रैदास का प्रभाव था। ब्रिटिश राज की शिक्षा और संस्कृति से स्त्री-पुरुष बराबरी का सबक सीखा। मराठी भाषा के प्रमुख भारतीय लेखक होने के साथ फुले की ख्याति सुधारक के रूप में फैल गई। 1872 में उन्होंने *गुलाम गिरी* लिखी। यह पुस्तक उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी 1948 में प्रकाशित हुई डॉ. आंबेडकर की पुस्तक द *अनटचेबल* थी।

कोलापुर के छत्रपति शाहू महाराज पर भी फुले के सत्यशोधक आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। उन्होंने 1902 में ही अपने राज्य की नौकरियों में अस्पृश्य व अति पिछड़ी जातियों के लिए पचास फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। बिना शर्त *मूकनायक* की सहायता करते हुए प्रवेशांक पर ही ढाई लाख रुपये की मदद की।

सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले के साथ 1840 में ब्याह कर आईं। वह उनकी महज पत्नी भर नहीं थीं, शिक्षा मिशन को आगे ले जाने वाली आधार स्तंभ थीं। सावित्री बाई के साथ शिक्षिका 'फातिमा शेख' को भी याद करना प्रासंगिक होगा। फातिमा मुस्लिम समाज से पहली शिक्षिका थीं, जो सावित्री से तो बड़ी थीं ही, फुले से भी तीन साल बड़ी थीं। आंबेडकर ने फुले से विद्या और सामाजिक सम्मान सीखा, शिक्षा को जाति-धर्म के भेदों से मुक्त उसे शुद्ध मानवीय बनाया। बुद्ध से संगठन सीखा, जो 'संघ' के रूप में स्थापित हुए थे। फुले से जो बात विद्या के रूप में गांठ बांधी, आजीवन विद्या को सर्वोपरि महत्व दिया।

ज्योतिबा फुले किसान जीवन के अंतर्विरोधों, जमींदारों और भूमिहीन किसानों के संबंधों को बखूबी समझते थे। उन्होंने अपने यथार्थपरक लेखन द्वारा गुलाम को गुलामी का एहसास कराया था।

वर्तमान में डॉ. आंबेडकर सभी दलों के प्रिय हो गए हैं। कोई उनकी लोकतांत्रिक अवधारणा का पक्ष प्रकट कर रहा है, तो कोई 'संविधान' को बचाने की बात कर रहा है। संसदीय लोकतंत्र की चर्चा बिना आंबेडकर की विधिक चेतना-ज्ञान, आशाओं और आशंकाओं को नजर अंदाज करके नहीं की जा सकती।

डॉ. आंबेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों की अनियंत्रित सत्ताओं के परिणामों से सीखा और समझा था। अंततः वे जनता द्वारा नियंत्रित सत्ता के प्रस्तावक बने। वह तानाशाही या एकाधिकावादी सत्ता के स्थान पर जनमत से चुनी जाने वाली सत्ता का सम्मान करते थे। वह स्त्री-पुरुष, धनी-निर्धन सभी के मत का मूल्य एक बराबर मानते थे।

विचारणीय है कि यदि आज आंबेडकर जीवित होते, तो मौजूदा चुनावी राजनीति पर क्या कहते? ज्ञात हो कि वह पहले चुनाव के परिणामों से ही निराश हो उठे थे। जीवन के आखिरी दिनों में वह भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं थे। उन्हें भय था कि यदि लोकतांत्रिक शिक्षा का अभाव रहा, तो मतदाता को बरगलाया जा सकता है, जो निष्पक्ष चुनाव कराने के सम्मुख एक बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित है।

-साहित्यकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर

edit@amarujala.com